RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 291
दि. 22.02.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

ग्रेटर नोएडा बनेगा भारत का 'सिलिकॉन वैली', पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आज भारत के तकनीकी इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड' (ल्उछ ग्रुप और फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम) के सेमीकंडक्टर डरअळ संयंत्र का शिलान्यास किया।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में स्थापित होने वाली यह उत्तर भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर यूनिट है। लगभग 3,706 करोड़ रुपये के निवेश वाली यह परियोजना न केवल उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक मैप पर लाएगी, बल्कि भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगी।

प्रधानमंत्री ने लाल किले की अपनी बात दोहराते हुए कहा कि भारत के पास अब रुकने या सुस्त होने का समय नहीं है। उन्होंने दिल्ली में हुए 'ग्लोबल अक इम्पैक्ट समिट' का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे पूरी दुनिया अब भारत की अकक्षमता और विजन की कायल हो चुकी है। पीएम के मुताबिक, भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल होने की कोशिश कर रहा है जिनके पास मॉडर्न वर्ल्ड को चलाने वाली प्रोसेसिंग पावर है।

इस मौके पर पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के सांसद होने के नाते अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ल्उछ और फॉक्सकॉन की यह फैक्ट्री उत्तर प्रदेश की पहचान एक 'टेक्नोलॉजी पावरहाउस' के रूप में स्थापित करेगी। यह प्लांट केवल एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि यूपी को सेमीकंडक्टर सिस्टम का केंद्र बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। इससे न केवल तकनीक को बढ़ावा मिलेगा बल्कि निवेश के नए रास्ते भी खुलेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जिस जेवर और ग्रेटर नोएडा के इलाके में कभी गोलियां चलती थीं और लोग सूरज डूबने के बाद घर से निकलने में डरते थे, आज वही इलाका देश का 'ज्वेल' (गहना) बन चुका है। योगी ने कहा कि जेवर अब अराजकता नहीं बल्कि विकास के लिए जाना जाता है और यहां की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रमाण है।

सीएम योगी ने दिल्ली के भारत मंडपम में हुए समिट की तारीफ करते हुए कहा कि इससे न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता का जीवन आसान और सुगम होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के उस विजन का आभार जताया जिसके कारण उत्तर प्रदेश को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (नई तकनीकों) का हब बनने का मौका मिला है। इस प्रोजेक्ट के साथ यूपी अब भारत की प्रगति में एक इंजन की तरह काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

योगी सरकार का डबल धमाका: 2.51 लाख किसानों को करोड़ों का मुआवजा, 45 हजार होमगार्ड भर्ती में 'आपदा मित्रों' को तरजीह

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को किसानों और युवाओं के हित में दो बड़े फैसले लिए।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को किसानों और युवाओं के हित में दो बड़े फैसले लिए। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ-2025) के तहत 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि वितरित की। इसके साथ ही, उन्होंने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा

रास्ता खोलते हुए यूपी में 45,000 होमगाड्र्स की भर्ती में 'आपदा मित्रों' को प्राथमिकता देने का ऐतिहासिक ऐलान किया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में आपदा मित्रों की सेवा स्वैच्छिक है, लेकिन होमगार्ड के रूप में शामिल होने पर उन्हें सरकार की ओर से नियमित मानदेय दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अब तक 19,000 आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किया है।

एनएच-167 : 14 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, 3 घंटे का सफर 90 मिनट में होगा

(जीएनएस)।

हैदराबाद-पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत नेशनल हाईवे 167 को फोर-लेन में अपडेट किया जा रहा है। गुदेबेल्लूर-महबूबनगर खंड को 4-लेन में अपग्रेड करने के प्रोजेक्ट को फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रीमंडल से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। यह प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इस कॉरिडोर के पूरा होने पर गोवा और तेलंगाना दोनों ही राज्यों की आर्थिक गतिविधियों को बूस्ट मिलने की उम्मीद है।

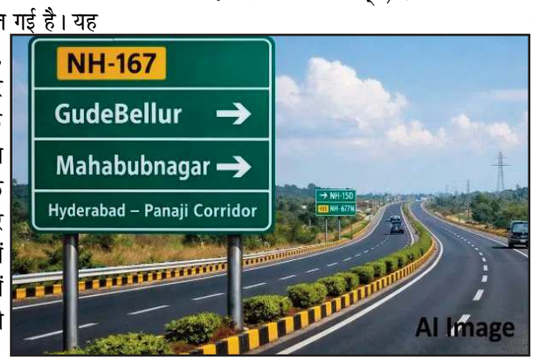

यह हाईवे गुदेबेल्लूर, मगनूर, मकतल, मारीकल, देवराकादरा, जकलैर, येलीगंडला और बंडेरपल्ली जैसे तेजी से विकसित हो रहे कस्बों से होकर गुजरता है। भीड़ कम करने और शहरी हिस्सों में ट्रैफिक सुगम बनाने के लिए 36.8 किमी लंबाई में बाईपास और रीअलाइनमेंट का प्रावधान किया गया है। परियोजना पूरी होने पर 3 घंटे का सफर घटकर करीब 1.5 घंटे रह जाने की उम्मीद है। इससे व्यापार और दैनिक आवाजाही दोनों को लाभ मिलेगा। रोजगार और उद्योगों को मिलेगा बूस्ट

- यह कॉरिडोर पीएम गतिशक्ति ढांचे के तहत 3 आर्थिक नोड्स, 9 सामाजिक नोड्स और 7 लॉजिस्टिक्स नोड्स को सीधा एक्सेस देगा।

- साथ ही, यह नेशनल हाईवे 150 और नेशनल हाईवे 167ठ से जाकर मिलेगा और हैदराबाद-बेंगलुरु कॉरिडोर तथा फार्मा और मेडिकल क्लस्टर्स तक पहुंच आसान बनाएगा। इससे निर्यात-से जुड़े उद्योगों और वेयरहाउसिंग गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है।

- परियोजना का निर्माण हाइब्रिड एन्युइटी मोड (ल्अट) पर किया जाएगा, जिसमें सरकार और निजी डेवलपर की संयुक्त भागीदारी होती है। यह मॉडल समयबद्ध निर्माण और वित्तीय जोखिम के संतुलन के लिए जाना जाता है। 14 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

रोजगार के मोर्चे पर भी यह प्रोजेक्ट अहम है। निर्माण चरण में लगभग 14.4 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 17.9 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। स्थानीय स्तर पर सप्लाई चेन बनाने, परिवहन और सहायक सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। यह अपग्रेड न केवल महबूबनगर क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देगा, बल्कि तेलंगाना को पश्चिमी तट से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग को भी मजबूत करेगा। रोजगार अवसरों के साथ ही यह प्रोजेक्ट अर्थव्यवस्था को भी गति देने वाला साबित हो सकता है।

अमित शाह बोले- 'हिंदी भारतीयों को जोड़ने वाली कड़ी'

गृहमंत्री अमित शाह ने अगरतला में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में हिंदी को लेकर चल रही बहस पर बड़ा बयान दिया। तमिलनाडु समेत कई दक्षिण भारतीय राज्यों में त्रिभाषा फॉमूर्ले का विरोध हो रहा है। इसे हिंदी थोपने की रणनीति बताई जा रही है।

इस बीच गृहमंत्री ने कहा कि जब हिंदी को बढ़ावा दिया जाता है, तो उससे देश की अन्य सभी भाषाएं भी मजबूत होती हैं। शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच किसी प्रकार का टकराव नहीं होना चाहिए। ये सभी भाषाएं एक ही मां की दो बहनों जैसी हैं।

जीत के लिए सीएम स्टालिन का डोर-टू-डोर कैंपेन प्लान, कार्यकताओं को दिया निर्देश! जनता से विनम्रता और सम्मान के साथ जुड़ने की कोशिश करनी है

(जीएनएस)।

तमिलनाडु में चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मदुरै में पार्टी कार्यकर्ताओं से घर-घर पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता से विनम्रता और सम्मान के साथ जुड़ने की कोशिश करनी है। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि पार्टी हर मतदाता से व्यक्तिगत संपर्क बनाने की कोशिश करेगी। प्रदेश में अप्रैल-मई में चुनाव होने वाले हैं और इस बार इंडिया अलायंस के सामने एनडीए गठबंधन की चुनौती है। एनडीएम में बीजेपी के साथ एआईएडीएमके और छोटी पार्टियां शामिल हैं। एक्टर से नेता बने विजय भी मैदान में हैं।

डीएमके सुप्रीमो और तमिलनाडु के सीएम ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को यह पक्का करना होगा कि चुनाव प्रचार के आखिरी क्षण तक हर परिवार से जाकर मुलाकात करें। जो लोग हमें वोट नहीं भी देते हैं, उनके यहां भी जाकर बातचीत करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, 'जनता ही असली मालिक है। हमें मतदाताओं के पास विनम्रता और स्नेह के साथ जाना चाहिए।"

उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि चुनाव को केवल राजनीतिक मुकाबले के रूप में न देखें, बल्कि जनता की सेवा के अवसर के रूप में लें।' मदुरै की रैली में उन्होंने महिला अधिकार सहायता योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव का बहाना बनाकर इस योजना को रोकने की साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा, कि हमारी सरकार ने इसका विरोध किया और महिलाओं को 5,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई। द्रविड़ मॉडल की सरकार महिलाओं, बच्चों, किसानों और समाज के सभी वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है।

स्टालिन ने कहा कि इन योजनाओं के कारण ही तमिलनाडु अभूतपूर्व विकास हासिल कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की प्रगति से विपक्षी दल परेशान और ईर्ष्या तक करने लगे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास ही उनकी सरकार की प्राथमिकता है।

चुनावी दौर में स्टालिन का यह बयान पार्टी कैडर को एकजुट करने और सरकार की उपलब्धियों को दोहराने की रणनीति का हिस्सा है। महिला सहायता योजना और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को चुनावी मुद्दा बनाकर सत्तारूढ़ दल मतदाताओं के बीच सकारात्मक संदेश देना चाहता है। मदुरै में दिया गया यह भाषण संकेत देता है कि सत्ताधारी दल विकास और कल्याणकारी योजनाओं को अपने चुनावी अभियान का केंद्रीय बिंदु बनाए हुए है।

'मेरा पैसा लौटाओ', सुप्रीमकोर्ट में करारी हार के बाद ट्रंप से मांगा रिफंड

(जीएनएस)।

अमेरिका की पॉलिटिक्स में इस हफ्ते जो हुआ, उसकी वाइब किसी Netflix पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं थी। Supreme Court of the United States ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा लगाए गए ट्रेड टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया। 6-3 के बहुमत से जस्टिसों ने कहा कि ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया और अपनी संवैधानिक सीमा लांघ दी। कोर्ट के मुताबिक, इन टैरिफ का असर सिर्फ ग्लोबल ट्रेड तक सीमित नहीं था- इसने घरेलू बाजार में

कीमतों को भी ऊपर धकेला। चीन और दूसरे देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट कम करना अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना

इसी सोच के तहत उन्होंने आपातकालीन शक्तियों के कानून का इस्तेमाल करते हुए कई देशों पर 'पारस्परिक' टैरिफ लगाए।

राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर विशेष आर्थिक कदम उठा सकते हैं। लेकिन टैक्स लगाने का मूल अधिकार अमेरिकी संविधान के अनुसार कांग्रेस के पास है यहीं से टैरिफ शुरू हुआ।

जम्मू-कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम, स्टोन क्रेशर के पास मिली संदिग्ध वस्तु, श्रीनगर-बांदीपोरा रोड बंद

जम्मू-कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम, स्टोन क्रेशर के पास मिली संदिग्ध वस्तु, श्रीनगर-बांदीपोरा रोड बंद

(जीएनएस)। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुरक्षाबलों ने एक संभावित आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। सफापोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक स्टोन क्रेशर के पास एक संदिग्ध वस्तु (र४२सूङ्ग४२ ड्डौ३) मिलने से हड़कंप मच गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बांदीपोरा-श्रीनगर वैकल्पिक मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियां और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच चुके हैं और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।

स्टोन क्रेशर के पास मिला संदिग्ध सामान

सफापोरा पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर एक स्टोन क्रेशर के पास संदिग्ध वस्तु देखी गई, जिसने सुरक्षाबलों के कान खड़े कर दिए। शुरूआती जानकारी मिलते ही पुलिस और सेना की संयुक्त टीमों ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया। यह स्थान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रशासन ने किसी भी संभावित जोखिम को कम करने के लिए तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और आसपास के लोगों को दूर कर दिया गया है।

श्रीनगर-बांदीपोरा वैकल्पिक मार्ग पूरी तरह बंद

सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, प्रशासन ने बांदीपोरा और श्रीनगर को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग को एहतियात के तौर पर ब्लॉक कर दिया है। इस सड़क पर ट्रैफिक की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है ताकि जांच के दौरान कोई नागरिक इसकी चपेट में न आए। मार्ग बंद होने से यात्रियों को थोड़ी असुविधा जरूर हो रही है, लेकिन सुरक्षाबलों का कहना है कि संदिग्ध वस्तु की पूरी तरह जांच होने तक रास्ता खोलना खतरनाक हो सकता है।

बम निरोधक दस्ता और सेना का संयुक्त अभियान

मौके पर बम निरोधक दस्ते की टीम पहुंच चुकी है, जो आधुनिक उपकरणों की मदद से संदिग्ध वस्तु की पहचान करने में जुटी है। स्थानीय पुलिस और सेना के जवान इलाके में सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई आईईडी हो सकता है, जिसे आतंकियों ने सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के लिए रखा होगा। फिलहाल जांच जारी है और आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार है।

आतंकी साजिश नाकाम करने की कोशिश

घाटी में पिछले कुछ समय से बढ़ रही संदिग्ध गतिविधियों के बीच गांदरबल की यह घटना सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर मानी जा रही है।

घरेलू हिंसा केस में गुजरात हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, 'पति का एक थप्पड़ मारना क्रूरता नहीं'

(जीएनएस)।

गुजरात हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक पुराने मामले में अहम टिप्पणी की है। इस केस में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि पति का पत्नी को मारा गया एक थप्पड़ अपने आप में 'क्रूरता' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। जब तक कि लगातार प्रताड़ना या गंभीर उत्पीड़न के पुख्ता सबूत मौजूद न हों, इसे हिंसा नहीं कह सकते। इस फैसले के बाद घरेलू हिंसा कानूनों की व्याख्या को लेकर नई बहस छिड़ गई है। यह मामला वलसाड जिले का है, जहां 1995 में शादी के कुछ महीनों बाद एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी।

मृतका के पिता ने आरोप लगाया था कि पति अक्सर देर रात घर आता था, पार्टियों में शामिल होता था और उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था। शिकायत में यह भी कहा गया कि जब महिला मायके में रह रही थी, तब पति वहां पहुंचा और उसे थप्पड़ मारा।

इसी आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया।

- साल 2003 में सेशन कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए क्रूरता के आरोप में एक वर्ष और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में सात वर्ष की सजा सुनाई थी। हालांकि, आरोपी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

- हाई कोर्ट ने मामले की दोबारा सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों का फिर से मूल्यांकन किया और पाया कि लगातार या असहनीय उत्पीड़न के पर्याप्त प्रमाण पेश नहीं किए गए।

- अदालत ने कहा कि केवल एक घटना के आधार पर किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उत्पीड़न और आत्महत्या के बीच सीधा और स्पष्ट संबंध साबित न हो।

अपने आदेश में अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मायके में बिना सूचना रुके रहने को लेकर विवाद हुआ था। इसमें पति के मारे गए सिर्फ एक थप्पड़ को कानूनी रूप से क्रूरता की परिभाषा में नहीं रखा जा सकता है।

पाकिस्तान के बन्नू में आत्मघाती धमाका, 2 सैनिक सहित 5 आतंकियों की मौत

पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में शनिवार को एक भीषण आत्मघाती हमले ने पूरे देश को दहला दिया है। सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में दो सैनिक शहीद हो गए,

जबकि सेना की जवाबी कार्रवाई और मुठभेड़ में पांच आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। यह हमला उस समय हुआ जब सेना एक 'इंटेलिजेंस-आधारित ऑपरेशन' चला रही थी।

आतंकियों ने एक विस्फोटक से लदी गाड़ी को सैन्य काफिले में टकरा दिया, जिससे भारी तबाही हुई।

सम्पादकीय

जय पवार ने विमान कंपनी वीएसआर के खिलाफ तत्काल सख्त कदम उठाने की मांग की

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार के विमान हादसे के करीब 20 दिन बाद उनके बेटे ने चुप्पी तोड़ी। अजित पवार के छोटे बेटे जय पवार ने एक बेहद भावुक पोस्ट के जरिए जांच पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जय पवार ने सीधे तौर पर कहा है कि विमान का ब्लैक बाक्स इतनी आसानी से नष्ट होने वाली चीज नहीं है। बता दें कि किसी भी विमान हादसे में जब सब वुछ नष्ट हो जाता है तो उसके अंदर ब्लैक बॉक्स न तो आग से, पानी से, जमीन पर गिरने से, विस्फोट से नष्ट नहीं होता। 20 वर्षो तक वह सुरक्षित रहता है। जय पवार ने साफ तौर पर कहा है कि ब्लैक बॉक्स इतनी आसानी से नष्ट होने वाली चीज नहीं है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। जनता को सब जानने का हक है। जय पवार ने सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने लिखा विमान दुर्घटना में ब्लैक बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं हो सकते। महाराष्ट्र की जनता को इस दिल दहला देने वाली दुर्घटना का पूरा, पारदर्शक और निर्विवाद सत्य जानने का अधिकार है। जय पवार ने विमान वंपनी वीएसआर के खिलाफ तत्काल सख्त कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस वंपनी के उड़ान व संचालन पर तुरन्त प्रातिबंध लगाया जाना चाहिए और विमानों के रखरखाव में हुईं संभावित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पोस्ट के अंत में उन्होंने बेहद भावुक होकर लिखा : मिस यू डैड। उधर अजित पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार ने कहा कि अजित दादा पवार की आकस्मिक मृत्यु में साजिश की आशंका है। रोहित पवार ने मुंबई में दावा किया कि कईं सूत्रों से विस्तृत जानकारी जुटाने के बाद ही वह प्रोस कांप्रोंस कर रहे हैं। प्रोस कांप्रोंस में रोहित पवार ने कहा कि उन्हें एयरलाइंस वंपनी वीएसआर, बुकिग संभालने वाली वंपनी एरो और पायलट सुमित कपूर पर संदेह हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में जानकारी इसलिए जुटानी पड़ी क्योंकि जांच एजेसियां बहुत धीमी गति से काम कर रही है। अजित दादा पवार परिवार और एनसीपी ने अब इस मामले की सीबीआईं जांच की मांग तेज कर दी है। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से मुलाकात कर इस मामले में उच्चस्तरीय जांच का निवेदन सौंपा है। प्रापुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ, सुनील तटकरे और पार्थ पवार जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में सरकार से मांग की गईं है कि इस हादसे के पीछे की हर साजिश या लापरवाही का पदार्फाश होना चाहिए। इनका सीधा निशाना उस एविएशन वंपनी पर है जिसका विमान इस हादसे का शिकार हुआ। आरोप लग रहे हैं कि क्या विमान की सर्विसिग और सुरक्षा मानकों में कोईं कोताही बरती गईं थी? 28 जनवरी को हुए इस हादसे में अजित दादा पवार सहित वुल 5 लोगों ने अपनी जान गंवाईं। इस घटना के बाद से ही यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह मात्र एक दुर्घटना थी या कोईं गहरी साजिश? आदरणीय अजित दादा पवार के आकस्मिक निधन से पूरे महाराष्ट्र को गहरा धक्का लगा है, यह कहना है सांसद सुप्रिया सुले का। एनसीपी (शरद गुट) ने मांग की है कि इस दुर्घटना की जांच पूरी होने तक नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू को उनके पद से हटा दिया जाए। हमारा भी मानना है कि इस मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र जांच आवश्यक है ताकि दुर्घटना के कारणों का साफ पता चले पर ऐसा होगा क्या?

'32 साल, 32 घंटे, ये फर्क है',अमित शाह से मिलते ही भूपेन बोरा का कांग्रेस पर वार, 8 मार्च को होगा खेला

(जीएनएस)।

चुनावी राज्य असम की राजनीति में आज (21 फरवरी) एक बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है- "32 साल बनाम 32 घंटे, फर्क साफ है।" यह बयान किसी आम कार्यकर्ता का नहीं, बल्कि लंबे समय तक कांग्रेस का चेहरा रहे भूपेन बोरा का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बोरा ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला और संकेत दिया कि यह तो सिर्फ शुरूआत है, आगे और भी नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं।

करीब तीन दशक तक कांग्रेस से जुड़े रहे भूपेन बोरा ने हाल ही में पार्टी से इस्तीफा दिया। वे 2021 से 2025 तक असम प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी रहे। ऐसे में उनका जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 22 फरवरी को वे औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं।

अमित शाह से मुलाकात के बाद बोरा ने कहा कि 32 साल तक कांग्रेस में रहने के बावजूद उन्हें जो सम्मान नहीं मिला, वह बीजेपी में 32 घंटे के भीतर मिल गया। उन्होंने गृह मंत्री और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा का आभार जताते हुए कहा कि परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है। इस मुलाकात में बैजयंत पांडा भी मौजूद थे।

भूपेन बोरा ने एक्स पर लिखा,

"32 साल बनाम 32 घंटे, ये फर्क साफ दिख रहा है। कल की मीटिंग के लिए गृह मंत्री अमित शाह और एक दिन पहले मेरे घर आने के लिए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का धन्यवाद हूं। बदलाव साफ दिख रहा

भूपेन बोरा बोले- '8 मार्च तक और आएंगे नेता'

ठउ्ळश चैनल से बातचीत में बोरा ने दावा किया कि 8 मार्च तक कई और कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद अमित शाह को इस बारे में जानकारी दी है। बोरा ने अमित शाह की रणनीतिक सोच की तारीफ करते हुए कहा कि वे सिर्फ वर्तमान राजनीति नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं।

उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर भी टिप्पणी की। बोरा का कहना था कि असम अभियानों के दौरान वे हमेशा उन्हें मुस्कुराते हुए देखते थे, लेकिन इस बार वे चिंतित

नजर आईं। वहीं गौरव गोगोई पर उन्होंने आरोप लगाया कि पहले उन्हें पार्टी का मजबूत स्तंभ बताया गया और बाद में उन्हीं पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए।

भूपेन बोरा की इस्तीफा का और कांग्रेस की चुनावी रणनीति

असम में चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए कांग्रेस ने गौरव गोगोई को अहम जिम्मेदारी दी थी। प्रियंका गांधी, मधुसूदन मिस्त्री और डीके शिवकुमार जैसे नेताओं को भी मोर्चे पर लगाया गया था। इसके बावजूद भूपने बोरा का इस्तीफा कांग्रेस के अभियान की रफ्तार पर असर डालता दिख रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बीजेपी ने यह 'ऑपरेशन' कैसे सफल कर लिया।

भूपेन बोरा की एंट्री को बीजेपी पूरी तरह भुनाने के मूड में है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने मुलाकात के बाद कहा कि भूपेन बोरा कांग्रेस के आखिरी हिंदू नेता थे। यह बयान अपने आप में सियासी संदेश देता है। सरमा पहले भी कह चुके हैं कि जो नेता विकास, स्थिरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में भरोसा रखते हैं, वे स्वेच्छा से बीजेपी में आ रहे हैं।

आगे क्या संकेत?

भूपेन बोरा का जाना सिर्फ एक नेता का पाला बदलना नहीं, बल्कि असम की राजनीति में शक्ति संतुलन के बदलने का संकेत माना जा रहा है। खासकर ऊपरी असम में बोरा का प्रभाव बीजेपी को चुनावी बढ़त दे सकता है।

अब निगाहें 22 फरवरी पर टिकी हैं, जब बोरा औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होंगे। उनका दावा है कि यह सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। ऐसे में सवाल बड़ा है- क्या कांग्रेस असम में इस झटके से उबर पाएगी, या '32 साल बनाम 32 घंटे' वाली लाइन आने वाले चुनावों की नई राजनीतिक कहानी लिख देगी।

बेंगलुरू से गोवा के लिए जल्द शुरू होगी वंदे भारत एक्सप्रेस, क्या होगा रूट और समय

(जीएनएस)।

बेंगलुरू से गोवा यात्रा करने वाले यात्रियों को जल्द बड़ा तोहफा मिलने वाला है। बेंगलुरू से गोवा के बीच में जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो सकती है। रेल मंत्रालय ने बेंगलुरु के यशवंतपुर और गोवा के मडगांव के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव दिया है।

हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा कोस्टल वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विस शुरू का ऐलान किया था, जिसके बाद रेलवे ने बेंगलुरू से गोवा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए प्रस्तापव भेज दिया है। आइए जानते हैं क्या होगा रूट और कितने घंटे में पूरा हो ये सफर?

यह सेवा मंगलुरु रेलवे क्षेत्र से होकर गुजरेगी, जिससे इस रूट पर यात्रियों को आधुनिक सुविधाएँ मिलेंगी। प्रस्तावित मार्ग के अनुसार, यह ट्रेन मंगलुरु जंक्शन और मंगलुरु सेंट्रल स्टेशनों को दरकिनार करते हुए पडिल बाईपास के रास्ते चलेगी।

बेंगलुरू से गोवा का सफर कितने घंटे में होगा पूरा?

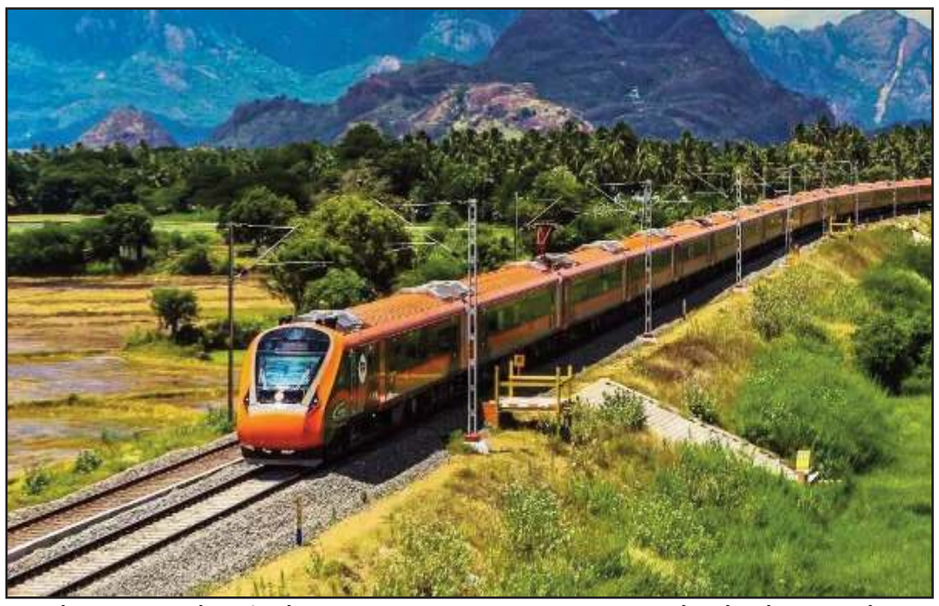

इस वंदे भारत एक्सप्रेस को एक दिशा की यात्रा पूरी करने में लगभग

13 घंटे का समय लगेगा, जिससे दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण शहरों से गोवा का सफर आसान हो जाएगा।

यशवंतपुर और मडगांव से चलेगी वंदे भारत

दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) ने स्पष्ट किया कि यदि ट्रेन मंगलुरु जंक्शन से चलाई जाती है, तो यात्रा का समय बढ़ जाएगा। इस सेवा के लिए दो वंदे भारत रेक की आवश्यकता होगी, एक यशवंतपुर से और दूसरी मडगांव से सुबह चलकर शाम तक अपने गंतव्य पर पहुंचेगी, ताकि सेवा की निरंतरता बनी रहे।

क्या होगा बेंगलुरू से गोवा वंदे भारत का समय?

हालांकि अभी समय नहीं निर्धारित किया गया है लेकिन अस्थायी समय सारणी के अनुसार, यशवंतपुर-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6:05 बजे यशवंतपुर (बेंगलुरु में) से रवाना होगी। यह दोपहर 2 बजे पडिल पहुंचकर शाम 7:15 बजे मडगांव में अपनी यात्रा समाप्त करेगी, जिसमें कुल 13 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा।

मडगांव से बेंगुलरू वापसी का क्या होगा रूट और समय?

मडगांव से वापसी की यात्रा में, मडगांव-यशवंतपुर वंदे भारत एक्सप्रेस गोवा के मडगांव से सुबह 5:30 बजे चलेगी और सुबह 11 बजे पडिल पहुंचेगी। यह ट्रेन शाम 6:40 बजे यशवंतपुर में अपनी यात्रा समाप्त करेगी। इस दिशा में भी यात्रा का कुल समय 13 घंटे 10 मिनट ही रहेगा।

रेल मंत्रालय ने बताया कि इस प्रस्तावित सर्विस की औसत गति 50 किमी प्रति घंटे से कम है। हालांकि, रहफ के अनुसार, चिकबनावरा और हसन के बीच गति सीमा 110 किमी प्रति घंटे से बढ़ाकर 130 किमी प्रति घंटे, और सकलेशपुर-सुब्रमण्य रोड घाट सेक्शन पर 30 किमी प्रति घंटे से बढ़ाकर 40 किमी प्रति घंटे करने के बाद इसकी रफ्तार बढ़ाई जा सकती है।

अंतिम शेड्यूल तय करने से पहले, रहफको ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (अएइ) प्रणाली से लैस दो वंदे भारत रेकों का उपयोग करके ट्रायल रन करने होंगे। इसके अलावा, हाल ही में विद्युतीकृत हसन-थोकुर (मंगलुरु) खंड में ओवरहेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट (डळए) प्रणाली को प्रमाणित और सक्रिय करना भी अनिवार्य है।

सेवा के समय सकलेशपुर घाट खंड पर 30 किमी प्रति घंटे की गति सीमा और ट्रेनों के क्रॉसिंग सहित प्रतिबंधों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए हैं। यह प्रावधान सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करता है, विशेषकर कठिन पहाड़ी मार्गों पर।

रहफ ने यशवंतपुर-हसन-यशवंतपुर खंड (174 किमी) पर प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए लगभग तीन घंटे (2.55 घंटे) आवंटित किए हैं। यह ङरफबेंगलुरु-कन्नूर एक्सप्रेस (16511/12) के 2.45/3 घंटे और ङरफ बेंगलुरु-कारवार पंचगंगा एक्सप्रेस (16595/96) के 2.30 घंटे के यात्रा समय से तुलनीय है।

प्राइवेट गाड़ियों की तुलना में कमर्शियल गाड़ियों में एक्सीडेंट की गंभीरता अधिक

लखनऊ, 21 फरवरी 2025: भारत का कमर्शियल गाड़ी सेगमेंट सिर्फ मोबिलिटी से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह इकोनॉमी के अलग-अलग सेक्टर को भी आपस में जोड़ता है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि मोटर इंश्योरेंस सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों से जुड़ा मसला है, लेकिन ऐसा नहीं है, कमर्शियल गाड़ियों के लिए भी प्रोटेक्शन उतना ही आवश्यक है। हर साल भारत में लगभग 30 लाख कमर्शियल वाहनों (जिनमें ट्रैक्टर और थ्री-व्हीलर भी शामिल हैं) का उत्पादन और बिक्री होती है। ये वाहन अनगिनत उद्योगों और उनके उत्पादों की आवाजाही को लगातार बनाए रखते हैं और अर्थव्यवस्था की रफ्तार को थामे रखते हैं। फिर भी, देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतना अहम यह क्षेत्र, देश में व्याप्त बीमा की कमी (अंडरइंश्योरेंस) की समस्या से अछूता नहीं है।

policybazaar.com®
HAR FAMILY HOGI INSURED

मोटर इंश्योरेंस एक कानूनी जरूरत है, लेकिन कमर्शियल सेगमेंट में अंडरइंश्योरेंस अक्सर बहुत कम थर्ड-पार्टी कवर, कम इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, या जरूरी ऐड-ऑन की कमी के रूप में होता है। सरकार और इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, माल ढुलाई ही भारत की जीडीपी का लगभग 14% है, जिसमें सड़क परिवहन देश के माल की मात्रा का 65% से ज्यादा हिस्सा ढोता है। एक ऐसे सेगमेंट के लिए जो कम मार्जिन और ज्यादा इस्तेमाल पर काम करता है, रिस्क और प्रोटेक्शन के बीच यह अंतर वल्नरेबिलिटी का एक बड़ा कारण बनता है।

कमर्शियल गाड़ियां अत्यावश्यक कैटेगरी में आती हैं। यहां हम बता रहे हैं कि उनका सही तरीके से इंश्योरेंस कैसे किया जा सकता है।

हाई-रिस्क, हाई लायबिलिटी सेगमेंट को कवर करना

कमर्शियल गाड़ियों अपनी बनावट और कामकाज के कारण अधिक रिस्क उठाते हैं। ये वाहन लंबी दूरी तय करते हैं, सालाना ज्यादा माइलेज देती हैं, कम डिलीवरी टाइमलाइन में चलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और सबसे जरूरी बात, ज्यादा लोड उठाती हैं। इन सब कारणों से प्राइवेट गाड़ियों की तुलना में कमर्शियल गाड़ियों में एक्सीडेंट की गंभीरता अधिक होती है, थर्ड-पार्टी लायबिलिटी का खतरा ज्यादा होता है और मरम्मत का खर्च भी काफी अधिक आता है।

इंडस्ट्री डेटा से पता चलता है कि कमर्शियल गाड़ियों का मोटर इंश्योरेंस क्लेम और ओन-डैमेज लॉस में काफी बड़ा हिस्सा होता है, भले ही उनकी संख्या टू-व्हीलर और कारों से कम हो। साथ ही, स्पेयर पार्ट्स की महंगाई, गाड़ी के ज्यादा डाउनटाइम और लायबिलिटी मामलों में ज्यादा कानूनी मुआवजे की वजह से क्लेम की लागत लगातार बढ़ रही है। इंश्योरेंस प्रीमियम उन रिस्क को दिखाते हैं जिन्हें कवर करने की जरूरत होती है।

कमर्शियल गाड़ियों में अंडरइंश्योरेंस और इससे होने वाला रिस्क

कई वाहन मालिकों के लिए इंश्योरेंस को एक कम्प्लायंस चेकबॉक्स के तौर पर देखा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कानून के तहत इसकी आवश्यकता है। अक्सर, वे कवरेज गैप को समझे बिना सबसे सस्ती पॉलिसी चुन लेते हैं। कुछ लोग लिमिटेड थर्ड-पार्टी कवर और कम आईडीवी चुन सकते हैं, तो कुछ लोग जीरो-डेप और रोडसाइड असिस्टेंस जैसे ऐड-ऑन नहीं ले पाते। जैसे-जैसे रिपेयर का खर्च बढ़ता है और गाड़ी की टेक्नोलॉजी ज्यादा मुश्किल होती जाती है, ये कमियां महंगी गलतियां बनती जा रही हैं।

रिन्यूअल के दौरान जो ₹2,000 की बचत लगती है, वह क्लेम के दौरान ₹1-2 लाख के आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च में बदल सकती है। कमर्शियल गाड़ी का इंश्योरेंस असल में बिजनेस को जारी रखने के बारे में है। एक भी एक्सीडेंट, चोरी या प्राकृतिक आपदा हफ्तों तक इनकम रोक सकती है। मालिक-ड्राइवरों के लिए, इसका मतलब तुरंत फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। फ्लीट ऑपरेटरों के लिए, यह डिलीवरी टाइमलाइन और कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियों को बिगाड़ सकता है। कई मामलों में, अंडरइंश्योरेंस खुद इंश्योरेंस से कहीं ज्यादा महंगा हो जाता है।

क्लेम का अनुभव प्रीमियम से ज्यादा क्यों मायने रखता है

कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम के समय अपनी कीमत साबित करती है। कमर्शियल गाड़ी का इंश्योरेंस भी इससे अलग नहीं है। इस सेगमेंट में डाउनटाइम अक्सर रिपेयर बिल से भी ज्यादा नुकसानदायक होता है। ट्रक या बस का कई दिनों या हफ्तों तक सड़क से गायब रहना सीधे तौर पर राजस्व के नुकसान, कॉन्ट्रैक्ट में रुकावट और बढ़ते फिक्स्ड खर्चों में बदल जाता है। देर से होने वाले सर्वे और डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कतों से रिपेयर का समय बिजनेस की क्षमता से कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए, पॉलिसी तय करने से पहले क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड, इंस्पेक्शन की स्पीड, कैशलेस गैरेज तक पहुंच और डेडिकेटेड कमर्शियल व्हीकल सपोर्ट की उपलब्धता का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्लेम के दौरान फेल होने वाला इंश्योरेंस अपने मकसद को ही खत्म कर देता है।

टेक्नोलॉजी और खरीदने में आसानी

सालों से, कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस आमतौर पर परमिट या फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करते समय लोकल एजेंट से खरीदा जाता रहा है। इस वजह से, मालिक अपने ऑप्शन की तुलना नहीं करते हैं और जो भी ऑफर किया जाता है या तुरंत उपलब्ध होता है, उसे खरीद लेते हैं। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाने से यह समीकरण बदल रहा है। टेक्नोलॉजी न केवल स्पीड देती है बल्कि किफायती और पूरी ट्रांसपेरेंसी भी देती है।

पॉलिसी एक दिन में जारी हो सकती है। इसके साथ ही, एक ही जगह पर कई इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी, कवरेज स्ट्रक्चर और कीमतों की तुलना करने की सुविधा उपलब्ध है। यह वॉल्यूम को देखते हुए फ्लीट मालिकों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है। समय के साथ, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन और यहां तक कि रिन्यूअल प्रोसेस भी कम हो जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म तेजी से पॉलिसी जारी करने, ट्रांसपेरेंट तुलना और ऑटोमेटेड रिन्यूअल ट्रैकिंग के जरिए फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन से क्लेम वर्कफ़्लो, कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन में सुधार हो रहा है, जिससे टर्नअराउंड टाइम कम करने में मदद मिल रही है।

भारत लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को तेजी से बढ़ा रहा है। इसलिए, कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस स्पेस को भी डेवलप करने की जरूरत है। क्लेम रिलायबिलिटी और टेक्नोलॉजी-लेड सर्विस प्रीमियम जैसे फैक्टर्स उतने ही जरूरी हैं। जिन ऑपरेटरों की रोजी-रोटी गाड़ियों के सड़क पर रहने पर निर्भर करती है, उनके लिए ऐसा इंश्योरेंस चुनना जो अच्छा काम करे, एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस फैसला बन जाता है।

नाइस फिल्म प्रोडक्शन ने निभाए अपने वादे

इंडियास आइकोनिक टैलेंट शो सीजन 1 के विनर और रनर अप को मिल रहा है बड़ा मंच

लखनऊ, नाइस फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले आयोजित इंडियास आइकोनिक टैलेंट शो सीजन-01 के ग्रैंड फिनाले (16 अगस्त 2025) में किया गया वादा अब हकीकत बन चुका है। शो के दौरान घोषणा की गई थी कि जो भी प्रतिभागी इस मंच से विजेता या रनर-अप बनकर निकलेंगे, उन्हें म्यूजिक वीडियो एल्बम के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा — और नाइस फिल्म प्रोडक्शन ने इस वादे को पूरा कर दिखाया है।सीजन-01 के प्रतिभागियों को मौका देते हुए अब तक 4 से अधिक म्यूजिक एल्बम लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें सिंगिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग और किड्स कैटेगरी के प्रतिभाशाली बच्चों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। लॉन्च हुए प्रमुख म्यूजिक एल्बम 'हवा हो गए' अमरेंद्र सिंह व शीतल कुशवाहा ने लीड रोल निभाया। 'तेरा लाल लहंगा' - किड्स कैटेगरी के फर्स्ट विनर एलिस रिहान सहित डांसिंग-मॉडलिंग के प्रतिभागी रुद्र प्रताप सिंह, इनाया दहल, आर्यन खान, अर्णव खान और अंशुमान गुर्जर ने लीड रोल किया।'कभी तुम्हें' - सिंगिंग कैटेगरी के विजेता ज्ञानेंद्र तिवारी और लीना चौहान की आवाज में रिलीज।'आसमान की तरफ' आर्यन खान, अर्णव खान और इनाया दहल की म्यूजिक स्टोरी वीडियो, जिसे दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया और रिलीज के कुछ ही दिनों में 5 लाख से अधिक व्यूज प्राप्त हुए। इन सभी गीतों को बड़े प्लेटफार्म पर लॉन्च किया गया है स्पॉटिफाई जिओ हंगामा एप्पल म्यूजिक मानी जानी म्यूजिक कंपनी में लॉन्च किया गया दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है और व्यूज लगातार लाखों में पहुंच रहे हैं। आगे की बड़ी योजना नाइस फिल्म प्रोडक्शन ने घोषणा की है कि आने वाले समय में उनके बैनर तले 100 से अधिक नए म्यूजिक एल्बम बनाए जाएंगे, जिनमें सिंगर, एक्टर, मॉडल और किड्स कैटेगरी के नए-नए प्रतिभागियों को मौका दिया जाएगा। इंडियास आइकोनिक टैलेंट शो सीजन-2.0 में भी चयनित प्रतिभाओं को इसी तरह लगातार लॉन्च किया जाएगा। नाइस फिल्म प्रोडक्शन के फाउंडर एवं डायरेक्टर अजीत श्रीवास्तव स्वयं एक प्लेबैक सिंगर हैं। उनकी मेहनत, लगन और विश्वास के दम पर आज इंडियाज आइकोनिक टैलेंट शो एक भरोसेमंद ब्रांड बन चुका है, जो नई प्रतिभाओं को सपनों से हकीकत तक पहुंचाने का काम कर रहा है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को केयरएज ईएसजी रेटिंग्स से 'केयरएज-ईएसजी 1+' ईएसजी रेटिंग प्राप्त हुई और बैंक को ईएसजी कार्य-निष्पादन हेतु 'लीडरशीप' श्रेणी में रखा गया

21 फरवरी, 2026: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गर्व से घोषणा करता है कि उसे केयरएज ईएसजी रेटिंग्स द्वारा "केयरएज-ईएसजी 1+" ईएसजी रेटिंग दी गई है, जिससे बैंक को उसके सुदृढ़ पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) कार्य-निष्पादन हेतु "लीडरशीप" श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है.

केयरएज-ईएसजी 1+ रेटिंग केयरएज द्वारा प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च ईएसजी सम्मानों में से एक है और यह संवहनीय बैंकिंग प्रथाओं, उत्तरदायी अभिशासन और सामाजिक रूप से समावेशी पहलों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दशार्ती है. यह सम्मान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपने कारोबार परिचालन, जोखिम प्रबंधन ढांचे और कार्यनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में ईएसजी सिद्धांतों के एकीकरण हेतु किए गए सक्रिय उपायों को प्रदर्शित करता है.

यह रेटिंग निम्नलिखित क्षेत्रों में बैंक के निरंतर प्रयासों को उजागर करती है

पर्यावरण के अनुकूल ऋण पद्धतियों को अपनाना

वित्तीय समावेशन और सामुदायिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना

सुदृढ़ अभिशासन संरचना और पारदर्शी प्रकटीकरण, उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन में ईएसजी पहलुओं का एकीकरण, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी संवहनीयता रूपरेखा को आगे बढ़ाने और भारत के व्यापक ईएसजी एजेंडा में सार्थक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है.

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

दुर्लभ न्यूरो-इंटरवेंशनल प्रक्रिया से ढाई वर्ष की बच्ची को मिल नया जीवन

– इंट्राक्रेनियल कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस पहली बार उत्तर प्रदेश में सफल

– राष्ट्रीय स्तर का पहला ऐसा मामला अपोलोमेडिक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ की टीम की बड़ी उपलब्धि

लखनऊ 21 फरवरी 2026: अपोलोमेडिक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक एक अत्यंत जटिल और दुर्लभ न्यूरो-इंटरवेंशनल प्रक्रिया इंट्राक्रेनियल कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस कर ढाई साल की बच्ची की जान बचाई। यह उन्नत मस्तिष्क प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में पहली बार की गई। इस प्रक्रिया को इंटरवेंशनल न्यूरो-रेडियोलॉजिस्ट डॉ. देवांश मिश्रा ने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी टीम के डॉ. अर्पित टौंक और डॉ. अमोल श्रीवास्तव के साथ मिलकर पूरी की।

बच्ची को अचानक बेहोशी, हाथ-पैरों में लकवा जैसे लक्षण और

बार-बार बेहोश होने की स्थिति में गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। आपातकालीन जांच में एमआरआई, सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी से मस्तिष्क की गहरी शिरा में खून का थक्का पाया गया। इस स्थिति को सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, जो समय पर उपचार न मिलने पर गंभीर मस्तिष्क को गहरे नुकसान या मृत्यु का कारण बन सकती है।बाल रोग विभाग की टीम ने प्रारंभ में स्टैंडर्ड इलाज शुरू किया। जिसमें डॉ. सिद्धार्थ कुँवर, डॉ. सिद्धार्थ और डॉ. निशांत गोपाल शामिल रहे। लेकिन स्थिति की गंभीरता और सीमित सुधार को देखते हुए चिकित्सकों ने इंट्राक्रेनियल कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस करने का फैसला लिया। इतनी कम उम्र के मरीज में यह प्रक्रिया बेहद दुर्लभ मानी जाती है।प्रक्रिया के दौरान पैर में एक छोटा छेद कर सूक्ष्म कैथेटर डाला गया और उसे रक्त वाहिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क की प्रभावित गहरी शिरा तक सावधानीपूर्वक पहुंचाया गया। इसके बाद थक्का घोलने वाली दवा सीधे उसी स्थान पर दी गई। चार दिनों तक लगातार निगरानी के साथ सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी की गई, जिसके बाद थक्का पूरी तरह घुल गया।इसके बाद बच्ची को इंटेंसिव केयर में रखा गया, धीरे-धीरे वेंटिलेटर से हटाया गया और विशेष चिकित्सा देखरेख जारी रही। लगभग तीन सप्ताह के उपचार के बाद उसे स्थिर अवस्था में छुट्टी दे दी गई। वर्तमान में वह चलने, बोलने और सामान्य दैनिक गतिविधियां करने में सक्षम है।

डॉ. देवांश मिश्रा ने कहा, 'मस्तिष्क की गहरी शिराओं में खून का थक्का बनना बच्चों में अत्यंत गंभीर और जानलेवा स्थिति होती है। इस प्रकार की प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा लिटरेचर में भी बहुत कम दर्ज है और उत्तर प्रदेश में यह पहला मामला है।'

चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं

(छगन लाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत.

चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई या कोई भी अन्य स्वायत्त संस्था जिसका सर्वोपरि कर्तव्य निष्पक्ष रूप से कार्य करना है। लेकिन जब इन संस्थाओं पर सवाल उठते हैं, और वह भी एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर, तो इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगते हैं। आज स्थिति ऐसी है कि ये संस्थाएं निष्पक्ष नहीं बल्कि पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करती हैं। और अधिकतर समय वे सत्ताधारी दल के इशारे पर काम करती हैं। जनता के एक वर्ग के मन में यही धारणा बन गई है।

यदि हम चुनाव आयोग की बात करें, तो यह देश की एक स्वायत्त संस्था है जिस पर देश के लोकतंत्र का स्वास्थ्य टिका हुआ है, लेकिन जब इसी संस्था पर पक्षपात के आरोप लगते हैं और यह साबित हो जाता है कि ऐसा हो रहा है और देश के सर्वोच्च न्यायालय को इसे बार-बार फटकार लगानी पड़ती है, तो यह न केवल चुनाव आयोग के लिए शर्म की बात है बल्कि देश के लोकतंत्र के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। दूसरे, चुनाव आयोग के इस तरह के विवादास्पद कार्यों को लेकर देश भर से जिस तरह की शिकायतें उठाई जा रही हैं, उससे स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग देश के सभी नागरिकों का विश्वास जीतने में पूरी तरह विफल रहा है।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग से सबसे महत्वपूर्ण अपेक्षाओं में से एक यह रही है कि यह पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए। कई विवादों के बीच विपक्षी दलों द्वारा भी यह एक प्रमुख मांग उठाई गई है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग का तर्क है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को हटाना है। इसमें वे लोग भी शामिल होंगे जो पलायन कर चुके हैं और जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इस उद्देश्य पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों के मतदाता सूची से बाहर किए जाने की खबरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसका मूल कारण पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी हो सकती है। जिसके कारण आम नागरिकों में कई चिंताएं पैदा हो गई हैं। यदि एसआईआर प्रक्रिया शुरू से अंत तक पूरी तरह से पारदर्शी होती, तो अनावश्यक विवादों से बचा जा सकता था।

और मतदाताओं को उनके लोकतांत्रिक मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह शिकायत उठाई जाती है कि देश के नागरिकों, और यहां तक कि एक विशेष समुदाय के लोगों को भी, बड़ी संख्या में मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो यह चुनाव आयोग की पूर्ण विफलता है, जो एक शर्मनाक बात है।

नेपाल के बाद सुलग रहा श्रीलंका, जेन-ज़ी नहीं साधु उतरे सरकार के खिलाफ, फिर होगा तख्तापलट?

श्रीलंका की राजधानी में बौद्ध भिक्षुओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि देश के बहुसंख्यक धर्म 'बौद्ध धर्म' और भिक्षुओं को बदनाम करने के लिए एक संगठित अभियान चलाया जा रहा है। भिक्षुओं का आरोप है कि यह सिर्फ सामान्य आलोचना नहीं है, बल्कि प्लानिंग के साथ किया जा रहा प्रयास है, जिससे बौद्ध धर्म की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके।

सरकार को दिया अल्टीमेटम

अपनी बरत रखते हुए भिक्षुओं ने 10-सूत्रीय मांग जारी किया है। उनका कहना है कि बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को 'राजनीतिक रूप से कमजोर' किया जा रहा है और इस पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो हालात सरकार की हद से बाहर सकते हैं।

क्या है मामला?

भिक्षुओं का दावा है कि निहित स्वार्थों द्वारा संगठित सोशल मीडिया अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनका मकसद बौद्ध धर्म और भिक्षुओं को बदनाम करना है। इस पर एक अन्य प्रमुख भिक्षु वेन कोट्टापोला रत्नपाला ने सरकार से इसे रोकने का आग्रह किया है। पिछले एक साल में कुछ राजनेताओं द्वारा खुले तौर पर बौद्ध भिक्षुओं की आलोचना भी की गई है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। और विवाद

जिलाधिकारी ने तहसील चायल में सुनी जनशिकायतें

जनपद कौशाम्बी के सभी तहसीलों में आज सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने तहसील चायल में जनशिकायतों को सुनकर सम्बन्धित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण व समयान्तर्गत निस्तारित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने राजस्व से सम्बन्धित शिकायतों पर राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर शिकायत को निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को तहसील दिवस में प्राप्त शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी शिकायत लम्बित न होने पाये। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर संबंधित अधिकारियों को ऑनलाइन आवेदन कराकर पात्रता की स्थिति में लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए।

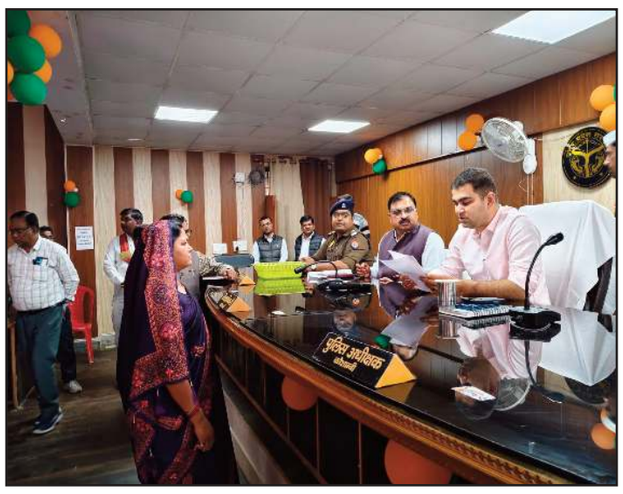

सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 45 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 01 शिकायत का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। तहसील मंझनपुर में कुल 16 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 02 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया तथा तहसील सिराथू में कुल 12 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 01 शिकायत का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया।

ओवरलोड डंपरों व अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप

(जीएनएस) कौशांबी

कौशांबी जनपद के थाना सैनी क्षेत्र में ओवरलोड डंपरों के संचालन को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि बालू एवं मिट्टी से लदे ओवरलोड वाहन तेज रफ्तार में सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे आम जनता की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है।

एक व्यक्ति द्वारा वीडियो बनाए जाने पर कथित रूप से सुनील तिवारी नामक व्यक्ति द्वारा धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकताओं का कहना है कि संबंधित व्यक्ति ने 'सब सेटिंग से चलता है' जैसी बात कही। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

वहीं थाना कोखराज के अंतर्गत भरवारी चौकी क्षेत्र में भी अवैध मिट्टी खनन जारी होने की शिकायत सामने आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना वैध अनुमति के लगातार खनन कार्य किया जा रहा है।क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि ओवरलोडिंग और अवैध खनन की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके और कानून व्यवस्था बनी रहे।

कोखराज थाने में पीस कमेटी की बैठक करते थानाध्यक्ष। छाया आज

समाचार लिखे जाने तक संबंधित विभागों की ओर से कोई आधिकारिक बयान प्राप्त नहीं हुआ था।

फरह पुलिस और स्वॉट टीम ने मुठभेड़ में 25 हजार के ईनामी लुटेरे को दोनों पैरों से किया लंगड़ा : अवैध हथियार, नगदी और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद

-ताबड़तोड़ महिलाओं के कानों से कुंडल लूटकर शातिरों ने पुलिस को दी थी चुनौती

मथुरा (जीएनएस)।थाना फरह क्षेत्र स्थित परखम रोड़ पर फरह पुलिस और स्वॉट टीम की 25 हजार के ईनामी कुख्यात बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में ईनामी बदमाश के दोनों पैरों में सरकारी पीतल धंस गई। पकड़ा गया ईनामी बदमाश, महिलाओं के कानों से कुंडल लूट की वारदातों में मुख्य आरोपी है। जानकारी के अनुसार एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देशन एवं एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा सीओ रिफाइनरी अनिल कपरवान के नेतृत्व में थाना प्रभारी फरह छोटेलाल और स्वॉट टीम प्रभारी अजय वर्मा पुलिस टीम के साथ महिलाओं के कानों से कुंडल छीनने वाले गैंग के ईनामी सरगना की तलाश में सुराग तलाश रहे थे। उसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि फरार चल रहा 25 हजार का ईनामी कुख्यात बदमाश कहीं भागने की फिराक में परखम रोड़ स्थित गोवर्धन नाले के पास खड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी छोटेलाल और स्वॉट टीम प्रभारी अजय वर्मा पुलिस टीम में कस्बा चौकी प्रभारी अजय सिंह मलिक, चौकी प्रभारी रैपुराजाट तेजेन्द्र सिंह, चौकी प्रभारी महुअन टोल प्लाजा अभिलाख सिंह, एसआई अमित चौहान, स्वॉट टीम के मुख्य आरक्षी हरजेंद्र सिंह, दुर्विजय सिंह, अखिल प्रताप सि, रमन चौधरी, योगेश कुमार, आशुतोष और थाना फरह के मुख्य आरक्षी सर्वेश सिंह, विनय कुमार, पंकज कुमार, सर्वेश सिंह, अखिलेश कुमार, राजकुमार तथा रोहित कुमार के साथ वहां पहुंच गए। फरह पुलिस और स्वॉट टीम ने ईनामी बदमाश को दबोचने के लिए संयुक्त रूप से घेराबंदी की तो शातिर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने जबावी

कार्रवाई की तो ईनामी बदमाश रामजीत पुत्र बृजलाल निवासी गांव पिपरौठ थाना फरह के दोनों पैरों में पुलिस की गोली धंस गईं। पुलिस टीम ने घायल बदमाश को गिरफ्तार करने के बाद ईलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने पकड़े गए ईनामी के कब्जे से 1 तमंचा, कारतूस, लूटे गए माल को बेचकर हिस्से में आए 24 हजार रूपए और घटना में प्रयुक्त पैशन-प्रो बाइक बरामद हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीओ रिफाइनरी अनिल कपरवान ने बताया कि मुठभेड़ में घायल हुए ईनामी बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर विगत 8 फरवरी को कुरकन्दा मोड़ पर, 13 फरवरी को हिन्दुस्तान कॉलेज के पास से, 15 फरवरी को फरह में ब्लॉक के पास और 18 फरवरी को मां की रसोई होटल के पास पीड़ित महिलाओं के कानों से कुंडल लूटे थे। बताया कि विगत 15 फरवरी को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल हुए ईनामी बदमाश रामजीत के साथी रवि पुत्र बाबूलाल और महेन्द्र उर्फ हल्के को मुठभेड़ में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में घायल हुए ईनामी बदमाश के ऊपर तीन दर्जन से अधिक गंभीर धाराओं में मुकदमें दर्ज है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज दिया है।

यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संस्था और छात्रों ने चलाया अभियान

अधिकारियों ने श्रमदान करके छात्रों को किया प्रेरित

मथुरा (जीएनएस)।श्रीकृष्ण की नगरी में यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए गऊघाट पर जिला प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं तथा छात्रों ने संयुक्त रुप से सफाई अभियान प्रारंभ किया है। इस बीच "यमुना क्लीन-अप ड्राइव' के माध्यम से न केवल घाटों की सफाई की गई बल्कि 'लेट्स सेव आवर रिवर' (अपनी नदी बचाओ) के नारे के साथ ब्रज मंडल को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया गया। अभियान में अधिकारियों ने निर्देश देने के साथ ही स्वयं हाथों में झाड़ू लेकर कूड़ा हटाते हुए श्रमदान किया। जानकारी के अनुसार मथुरा-वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त जगप्रवेश, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सूरज पटेल और अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह ने सबसे आगे श्रमदान करके युवाओं को यमुना के स्वच्छता अभियान में अनवरत शामिल होने के लिए प्रेरित किया। यह स्वच्छता अभियान नगर निगम प्रशासन, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, लिविंग पीस प्रोजेक्ट्स फाउंडेशन और वैल्यूसेंट फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में चलाया गया। कार्यक्रम में लिविंग पीस प्रोजेक्ट्स फाउंडेशन की अध्यक्ष ब्रिगिट मैडलीन

वैन बेरेन की मौजूदगी ने स्वच्छता अभियान को अंतरराष्ट्रीय पटल पर पहचान दी है। इस मौके पर तकनीकी निदेशक बारोरुचि मिश्रा और सलाहकार डा. विकास चतुर्वेदी (सीए) ने भी यमुना संरक्षण के लिए तकनीकी और सामाजिक ढांचे पर बल दिया। इसी के साथ गुड़गांव के पाथवेज वर्ल्ड स्कूल और मथुरा-वृंदावन के कन्हा माखन स्कूल के छात्र-छात्राओं ने जिस ऊर्जा के साथ यमुना घाट की सफाई की, उससे यह भरोसा हुआ कि आने वाली पीढ़ी अपनी विरासत को बचाने के लिए जागरूक हो रही है। इस मौके पर नगर आयुक्त जग प्रवेश ने कहा कि श्रीधाम मथुरा-वृंदावन, विश्व के प्रमुख तीर्थ हैं। कहा कि जब विद्यार्थी ऐसे अभियानों से जुड़ते हैं तो स्वच्छता की गूंज समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश बृज तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सूरज पटेल ने कहा कि घाटों की स्वच्छता केवल सरकार का काम नहीं, बल्कि यह हम सभी की जिम्मेदारी और भक्ति का भाव है। इस बीच सफाई अभियान में नगर निगम के जोनल सेनेटरी ऑफिसर, क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक, किंग ग्रुप और नेचर ग्रीन के कर्मचारी भी पूरी साथ में जुटे रहे। स्वच्छता अभियान के समापन पर मौजूद सभी अधिकारी, स्वंयसेवी संस्था और छात्रों ने यमुना को हमेशा स्वच्छ रखने की शपथ ली।

चतुर्वेदी समाज धूमधाम से निकालेगा तीन मार्च को होली का डोला

मथुरा (जीएनएस)।ब्रज में रंगोत्सव की धूम प्रारंभ हो चुकी है। श्रीकृष्ण की नगरी विभिन्न स्थानों पर होली के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस बीच चतुर्वेदी समाज भी आगामी तीन मार्च को धूमधाम से होली का डोला निकालेगा। इस संबंध में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक एवं माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक द्वारा चतुर्वेदी समाजवाडी में प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार चतुर्वेदी समाज का होली डोला बहुत ही भव्यता के साथ सामाजिक रीति-रिवाज एवं ठाकुर जी के स्वरूप के अनुसार निकाला जाएगा। इस डोले में चतुर्वेदी समाज के लोग होली की गाने गाते हुए निकलेंगे। बताया कि डोले में भारतवर्ष और विदेश से भी तीर्थयात्री आते हैं। इसलिए श्री पाठक

ने यह सभी लोगों से अपील करते हुए कहा की किसी भी तीर्थयात्री के साथ कोई अभद्रता ना हो और सभी लोग केवल टेशू के फूल के रंग व अबीर गुलाल ही उड़ाएं, किसी भी प्रकार के गीले रंग या सादा पानी किसी के ऊपर ना डालें। प्रेसवार्ता का संचालन करते हुए माथुर चतुर्वेद परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि मेले को भव्य बनाने के लिए क्रमबद्ध तरीके से सभी झांकियों को डीजे पर लगाया जाएगा और युवा समिति और परिषद के पदाधिकारीयों को पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी तथा मेले को चार भागों में विभाजित किया जाएगा। कहा कि द्वारकाधीश मंदिर से होलीगेट तक की जिम्मेदारी अलग दी जाएगी और होलीगेट से कोतवाली रोड़ तक की जिम्मेदारी तथा भरतपुर गेट से चौक बाजार व चौक बाजार से विश्राम घाट तक चार भागों में मेले को बांटा जाएगा। इस अवसर पर संरक्षक नवीन नागर, गरधारीलाल पाठक, उमाकांत चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष संजय चतुर्वेदी, मनोज चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष कमल चतुर्वेदी, मनीष चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष दुबई शाखा नीरज चतुर्वेदी, संजय मंत्री, मनोज पाठक, रितेश पाठक सौरभ चतुर्वेदी, सोनू चतुर्वेदी, गोपाल बौहरे युवा समिति अध्यक्ष, सौरभ अभिषेक चतुर्वेदी और सौरभ चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में ब्रज विकास परिषद का भी सहयोग रहता है।

उमा मोटर्स पर मारुति की पहली इलैक्ट्रिक एसयूवी ई-विटारा हुई लांच

सिंगल चार्ज में चलेगी साढ़े पांच सौ किमी.

मथुरा (जीएनएस)।राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित उमा मोटर्स नेक्सा शोरूम में हुए कार्यक्रम में ऑटोमोबाईल जगत में हलचल मचा दी है। काफी समय से इंतजार कर रहे लोगों के बीच मारुति सुजुकी की पहली पूर्णतः इलैक्ट्रिक एसयूवी ई-विटारा का अनावरण किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी और उमा मोटर्स के एमडी पवन चतुर्वेदी ने दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर किया। इस अवसर पर ब्रजबिहार ग्रुप के ब्रह्मानंद चतुर्वेदी, ब्रज हीरो के निदेशक विजय चतुर्वेदी, उमा मोटर्स के निदेशक गौरव चतुर्वेदी, पीयूष चतुर्वेदी और पार्थ चतुर्वेदी ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर विस्टा आर्किटेक्ट्स के समर्थ चतुर्वेदी समेत प्रतिष्ठित उद्यमी और ऑटोमोबाइल प्रेमी मौजूद रहे। इस अवसर पर उमा मोटर्स के निदेशक

पीयूष चतुर्वेदी ने बताया कि लांच हुई ई-विटारा, मारुति सुजुकी कंपनी की तकनीक और भरोसे का नया चेहरा है। लांच हुई ई-विटारा की प्रारंभिक एक्स शोरूम कीमत 10 लाख 99 हजार से 19 लाख 99 हजार तक है। बताया कि एक बार में फुल चार्ज होने पर यह 550 किमी. की दूरी तय करेगी। इसी के साथ डीसी फास्ट चार्जर से मात्र 45 से 50 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज होती है। ई-विटारा कार में 10.25 इंच टचस्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा और वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर मिलेंगे। इस मॉडल में 40.5 किलोवाट, घंटा की उन्नत बैटरी दी गई है। इसके साथ ही एलईडी हेडलाइट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और स्मार्टफोन एप कंट्रोल जैसी सुविधाएं इसे भविष्य की बेहतर कार बनाती हैं। लांच के दौरान ग्राहकों का उत्साह देखने लायक था। इस मौके पर चोला फाइनेंस के डिविजनल मैनेजर मोहित, केनरा बैंक के डिविजनल मैनेजर मानस, सेल्स मैनेजर सौरभ भाटिया और दीपक चौधरी भी शामिल हुए। पर्यावरण के जानकारों का मानना है कि ई-विटारा का आगमन पर्यावरण संरक्षण और इलैक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

नौहझील पुलिस ने फरार चल रहे बदमाश को दबोचा : अवैध हथियार और कारतूस बरामद

मथुरा (जीएनएस)।थाना नौहझील क्षेत्र स्थित पारसौली के पास से पुलिस ने फरार चल रहे बदमाश को अवैध हथियार समेत दबोच लिया। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी नौहझील सोनू सिंह पुलिस टीम के साथ वांछित अपराधियों की तलाश में जुटे हुए थे। उसी दौरान उन्हें

मुखबिर से सूचना मिली कि फरार चल रहा एक बदमाश कहीं भागने की फिराक में गांव पारसौली के पास खड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सोनू सिंह पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे वांछित अपराधी रोबिन पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी गांव जरैलिया थाना नौहझील को घेराबंदी करके दबोच लिया। पुलिस ने पकड़े

पुलिस ने मादक पदार्थ समेत एक तस्कर को किया गिरफ्तार

मथुरा (जीएनएस)।थाना नौहझील क्षेत्र स्थित रायपुर रोड़ से पुलिस ने एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी नौहझील सोनू सिंह और एसआई विदित अम्बावत पुलिस टीम के साथ संदिग्धों की चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि गांव रायपुर रोड़ पर एक मादक पदार्थ तस्कर गांजा बेच रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सोनू सिंह और एसआई विदित अम्बावत पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे तस्कर हरेन्द्र पुत्र झंकी निवासी गांव बरौठ थाना नौहझील को दौड़ाकर पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़े गए तस्कर की तलाशी ली तो उसके पास से 3 सौ 47 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करके जेल न्यायालय भेज दिया है।

जहां दवाएं रुक जाएं, वहां सर्जरी उम्मीद बनती है

– लखनऊ में उन्नत मिर्गी सर्जरी पर जागरूकता कार्यक्रम

– विशेषज्ञों ने कहा, डरें नहीं, सही जानकारी है सबसे बड़ा इलाज

लखनऊ, 21 फरवरी, 2026: मिर्गी को लेकर समाज में आज भी कई तरह के भ्रम और डर मौजूद हैं, जबकि यह मस्तिष्क से जुड़ा सामान्य रोग है जिसका इलाज संभव है। इसी उद्देश्य से लखनऊ में आयोजित जन-जागरूकता कार्यक्रम में अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कोच्चि के एडवांस्ड एपिलेप्सी सेंटर के निदेशक डॉ. सिबी गोपीनाथ और मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर न्यूरोलॉजी डॉ. अनूप कुमार ठक्कर ने मिर्गी सर्जरी के महत्व पर विस्तार से चर्चा की।भारत में लगभग 1.50 करोड़ लोग मिर्गी से प्रभावित हैं। अच्छी बात यह है कि सही दवाओं से 70 प्रतिशत से अधिक मरीजों में दौरे पूरी तरह नियंत्रित हो जाते हैं। लेकिन लगभग 30 प्रतिशत मरीज ऐसे होते हैं जिन के लिए दवाएं असर नहीं करतीं। ऐसे मामलों में सर्जरी सुरक्षित और प्रभावी विकल्प हो सकती है।

डॉ. सिबी गोपीनाथ ने कहा, 'मिर्गी सर्जरी डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। सही जांच के बाद चुने गए मरीजों में सर्जरी से दौरा-मुक्त जीवन संभव है। कई मरीजों में ऑपरेशन के बाद दवाएं भी धीरे-धीरे बंद की जा सकती हैं।'डॉ अनूप कुमार ठक्कर ने बताया, 'जहां दवाएं काम न करें, वहां मिर्गी सर्जरी आशा देती है। यह खर्च नहीं, जीवन में निवेश है। हम पहले यह सुनिश्चित करते हैं कि दौरे मस्तिष्क के किस हिस्से से शुरू हो रहे हैं, फिर उसी के अनुसार इलाज की योजना बनाई जाती है।'विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर चार में से तीन मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। अंधविश्वास, सामाजिक कलंक और जानकारी की कमी इसके बड़े कारण हैं। अनुमान है कि देश में लगभग 50 लाख मरीज सर्जरी के योग्य हो सकते हैं लेकिन हर साल केवल करीब 1,000 सर्जरी ही हो पाती हैं।

आधुनिक जांच तकनीकों से यह पता लगाया जा सकता है कि दौरे मस्तिष्क के किस हिस्से से शुरू हो रहे हैं लेकिन ऐसी सुविधाएँ देश के गिने-चुने उन्नत केंद्रों तक सीमित हैं। दूरी, खर्च और स्थानीय संसाधनों की कमी के कारण अधिकांश मरीज वहाँ पहुँच नहीं पाते। अनुमान है कि देश में लगभग 50 लाख लोग सर्जरी के योग्य हो सकते हैं इसलिए जागरूकता बेहद जरूरी है।

कार्यक्रम में यह संदेश दिया गया कि हर मिर्गी लाइलाज नहीं होती। सही समय पर सही केंद्र में जांच और परामर्श से हजारों मरीज सामान्य और सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। लखनऊ में विशेषज्ञों की यह पहल उत्तर भारत में उन्नत मिर्गी सर्जरी सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

मिल्कीपुर विधायक चन्द्रभानु पासवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की शिष्टाचार भेंट

लखनऊ । जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक चन्द्रभानु पासवान ने लखनऊ में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उनकी पत्नी एवं अयोध्या जिला पंचायत सदस्य श्रीमती कंचन पासवान भी उपस्थित रहीं। भेंट के दौरान विधायक चन्द्रभानु पासवान ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुख्यमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने क्षेत्र में सड़कों, पेयजल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित योजनाओं को गति देने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक की बातों को गंभीरता से सुनते हुए क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जन-समस्याओं के त्वरित समाधान और विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस शिष्टाचार भेंट को मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर भी इस मुलाकात को सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय विकास कार्यों को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है

'पहले राजनीति का A,B,C तो सीखिए', मैथिली ठाकुर के 'धृतराष्ट्र' वाले बयान पर भड़के तेजस्वी यादव

बिहार विधानसभा के बजट सत्र में वार-पलटवार का दौर अब व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गया है। अलीनगर से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर द्वारा लालू प्रसाद यादव की तुलना 'धृतराष्ट्र' से करने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उबल पड़े हैं।

तेजस्वी ने न केवल मैथिली ठाकुर के अनुभव पर सवाल उठाए, बल्कि उन्हें आईना दिखाते हुए कानून-व्यवस्था और दलितों के मुद्दे पर घेरा। बिना नाम लिए किए गए इस हमले ने बिहार की सियासत में 'जंगलराज' बनाम 'महाभारत' की एक नई जंग छेड़ दी है, जिससे आने वाले दिनों में सदन और सड़क दोनों पर हंगामा बढ़ना तय है।

भाजपा की पहली बार विधायक बनीं मैथिली ठाकुर ने सदन में बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के रिश्तों की तुलना महाभारत के धृतराष्ट्र और दुर्योधन से कर दी। उन्होंने संकेत दिया कि पुत्र मोह में बिहार को पुराने दौर (2005 से पहले) में धकेला गया। हालांकि उन्होंने किसी का सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। इसी 'कटाक्ष' ने तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया पर मोर्चा खोलने के लिए मजबूर कर दिया, जहां उन्होंने विधायक को राजनीति का 'ककहरा' सीखने की सलाह दे डाली।

जिलाधिकारी के निर्देश पर दिव्यांग सेबू को प्रकाश किरण इण्टरनेशनल स्कूल में दिलाया गया प्रवेश

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने कान की मशीन किया प्रदान

जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल की अध्यक्षता में दिनांक 19.02.2026 को विकास खण्ड मूरतगंज की ग्राम पंचायत-रसूलपुर बदले में आयोजित ग्राम चौपाल में जनसुनवाई के दौरान एक मूकबधिर दिव्यांग सेबू पुत्र लईकउद्दीन निवासी ग्राम- रसूलपुर बदले द्वारा किसी भी विद्यालय में प्रवेश दिलाए जाने की मांग की गई थी। जिलाधिकारी ने जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को निर्देशित किया था कि दिव्यांग सेबू को जनपद के किसी भी दिव्यांग विशेष विद्यालय में प्रवेश दिलाई जाय एवं आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण भी उपलब्ध कराई जाय।

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने दिव्यांग सेबू को दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय प्रकाश किरण इण्टरनेशनल स्कूल, सैयद सरावां में प्रवेश दिलाया गया तथा तत्काल कान की मशीन प्रदान की गई। कान की मशीन पाकर दिव्यांग सेबू अत्यन्त खुश हो गया। इसके साथ ही दिव्यांग सेबू का आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करा दिया गया है।

जिलाधिकारी ने जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को निर्देशित किया है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि जनपद में कोई भी दिव्यांगजन पेंशन, कृत्रिम सहायक उपकरण एवं दिव्यांगजनों के लिए संचालित किसी भी सरकारी सहायता से वंचित न रहने पाए।

त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का वृहद् पुनरीक्षण कराए जाने के लिए समय सारिणी जारी

जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) डॉ. अमित पाल ने राज्य निर्वाचन आयोग उ.प्र. की अधिसूचना (संशोधन) के क्रम में जनपद कौशाम्बी की त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का वृहद् पुनरीक्षण कराए जाने के लिए समय सारिणी निर्धारित की जाती है।

दावे/आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त हस्तलिखित पाण्डुलिपियां तैयार करना, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना एवं सम्भावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन/निस्तारण की कार्यवाही करने की अवधि दिनांक 07 जनवरी, 2026 से 16 मार्च, 2026 तक निर्धारित की गई है। इसी प्रकार दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की कम्प्यूटरीकरण की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथास्थान समाहित करने एवं यथावश्यक मतदान केन्द्रों/स्थलों के निर्धारण की कार्यवाही दिनांक 21 फरवरी, 2026 से 16 मार्च,2026 तक, मतदाता सूचियों की कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र / स्थलों का कमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डो की मैपिंग, मतदाता कमांकन, रश्ठ आवंटन, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियां कराने आदि दिनांक 17 मार्च, 2026 से 13 अप्रैल, 2026 तक तथा निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन 15 अप्रैल, 2026 को किया जाएगा।

त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र०, लखनऊ के निदेशन एवं नियंत्रण में तैयार की जायेंगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के संशोधित पुनरीक्षण कार्यकम का सार्वजनिक जानकारी के लिए समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगें। निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

अब शान से चला सकेंगे विदेश में अपनी गाड़ी! उ.प्र. सरकार ने खत्म की सालों पुरानी बड़ी टेंशन

(जीएनएस)।

अगर आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं और वहां की सड़कों पर खुद गाड़ी चलाने का शौक रखते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको एक बड़ी राहत दी है। प्रदेश में अब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट एक प्रोफेशनल 'बुकलेट' के रूप में जारी किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के इतिहास में यह पहली बार है जब आईडीपी को बुकलेट फॉर्म में जारी करने की पुख्ता व्यवस्था लागू की गई है।

इससे पहले तक यूपी में आईडीपी को एक साधारण कागज पर प्रिंट करके दिया जाता था। इस कागजी परमिट के कारण कई विकसित देशों, विशेषकर जापान और अमेरिका में यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वहां के सुरक्षा अधिकारी अक्सर कागज की वैधता को लेकर आपत्तियां उठाते थे। अब नई बुकलेट व्यवस्था लागू होने से इन अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का स्थायी समाधान हो जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय मानक नई बुकलेट को वैश्विक नियमों के अनुरूप तैयार किया गया है ताकि विदेशों में जांच के दौरान कोई आपत्ति न हो।

हस्तलिखित शैली सुरक्षा और मानकों को ध्यान में रखते हुए बुकलेट में विवरण कर्सिव राइटिंग में भरा जाएगा। एक वर्ष की वैधता यह इंटरनेशनल परमिट जारी होने की तिथि से केवल एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।

दफ्तरों के चक्करों से मुक्तिः परमिट के स्वरूप को लेकर होने वाली शिकायतों और आरटीओ के बार-बार चक्कर लगाने की समस्या अब समाप्त हो जाएगी।

जिलों को बुकलेट का आवंटन (पूरी लिस्ट):

शासन ने प्रदेशभर के लिए कुल 4130 बुकलेट जारी की हैं। नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ जैसे शहरों को सबसे अधिक कोटा आवंटित किया गया है। किस जिले को कितनी बुकलेट मिली हैं, उसका पूरा विवरण यहां देखें: 1. नोएडा (यूपी-16): 750 बुकलेट 2. गाजियाबाद (यूपी-14): 500 बुकलेट 3. लखनऊ (यूपी-32): 350 बुकलेट 4. मेरठ (यूपी-15): 200 बुकलेट 5. कानपुर नगर (यूपी-78): 200 बुकलेट 6. आगरा (यूपी-80): 150 बुकलेट 7. सहारनपुर (यूपी-11): 65 बुकलेट 8. मुरादाबाद (यूपी-21): 50 बुकलेट 9. मुजफ्फरनगर (यूपी-12): 50 बुकलेट

10. बुलंदशहर (यूपी-13): 30 बुकलेट

11. बिजनौर (यूपी-20): 25 बुकलेट

होली से पहले आएगी किसान योजना की किस्त, लिस्ट में ऐसे चेक करें नाम

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खुशखबरी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य बजट 2026 में इस योजना के लिए ₹5,500 करोड़ आवंटित किए जाने के बाद, अब माना जा रहा है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च की शुरूआत में किसानों के खातों में ₹2,000 की राशि क्रेडिट कर दी जाएगी।

हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। राज्य के लगभग 83 लाख पात्र किसानों को इस किस्त का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि 13वीं किस्त के बाद से काफी समय बीत चुका है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, उट किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त के तहत राज्य के करीब 83 लाख किसानों को ₹2,000 प्रति किसान की राशि सीधे बैंक अकाउंट में उझळ के जरिए भेजी जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर किस्त जारी करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लाभार्थी सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त भी अभी जारी नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ढट किसान के साथ 'डबल बेनिफिट' मिल सकता है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भी फरवरी-मार्च के बीच आनी है।

यदि दोनों किस्तें साथ आती हैं, तो किसानों को एक साथ ₹4,000 का लाभ मिलेगा। इसी वजह से किसान दोनों योजनाओं की किस्तों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं

पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करें।

होमपेज पर "मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना" के डैशबोर्ड में जाकर विकल्प पर क्लिक करें।

क्षेत्रीय जानकारी भरें: अपना जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव का नाम ड्रॉपडाउन मेनू से चुनें।

सर्च करें: सारी जानकारी भरने के बाद क्लिक करें। आपके गांव की पूरी सूची सामने आ जाएगी। अगर आपका नाम लिस्ट में मौजूद है, तो आपको 14वीं किस्त का लाभ मिलना तय है।

यदि आपका नाम लिस्ट में है, तो अपना व्यक्तिगत स्टेटस भी चेक करें। यदि सब सही दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी किस्त बिना किसी रुकावट के खाते में पहुंच जाएगी। यदि स्टेटस में 'Pending' 'Rejected' दिख रहा है, तो तुरंत अपने क्षेत्रीय पटवारी या तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

4 दशक बाद स्क्रीन पर साथ दिखे रजनीकांत और कमल हासन, सुपरस्टार्स का दिखा स्वैगर अंदाज

(जीएनएस)।

एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं। करीब 47 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इन दो दिग्गजों की जोड़ी वापसी कर रही है। इस खबर ने दक्षिण भारतीय सिनेमा ही नहीं, बल्कि पूरे देश के फिल्म प्रेमियों के बीच उत्साह की लहर पैदा कर दी है। प्रशंसक लंबे समय से दोनों सुपरस्टार्स को एक साथ देखने का इंतजार कर रहे थे।

'KH x RK' का प्रोमो जारी

इस हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट को फिलहाल 'KH x RK' कोडनेम दिया गया है। फिल्म का निर्देशन Nelson Dilipkumar कर रहे हैं। हाल ही में जारी प्रोमो वीडियो में दोनों कलाकार एक्शन अंदाज में दिखाई देते हैं। यह छोटा लेकिन प्रभावशाली वीडियो दर्शकों के लिए एक खास संदेश की तरह है, जिसने फिल्म को लेकर जिज्ञासा और बढ़ा दी है।

गैरेज सीन और रेट्रो म्यूजिक

प्रोमो में कमल हासन और रजनीकांत एक गैरेज में साथ चलते

हुए नजर आते हैं। बैकग्राउंड में Anfirudh Ravichander का रेट्रो स्टाइल संगीत माहौल को खास बनाता है। दृश्य में रजनीकांत अपने विशिष्ट अंदाज में कार की चाबी कमल हासन को सौंपते हैं, जिसके बाद कमल ड्राइवर सीट संभालते हैं। यह प्रतीकात्मक क्षण दोनों सितारों की केमिस्ट्री और फिल्म की टोन का संकेत देता है। नेल्सन दिलीपकुमार ने प्रोमो को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर साझा करते हुए इस प्रोजेक्ट को लेकर सम्मान और खुशी व्यक्त की। उनकी पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर प्रशंसकों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। फिल्म इंडस्ट्री में भी इस सहयोग को ऐतिहासिक माना जा रहा है।

कहानी में अपराध और पुरानी यादें

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म की कहानी दो पुराने गैंगस्टरों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो वर्षों बाद एक कठिन परिस्थिति में फिर मिलते हैं। उनकी मुलाकात से बीते संघर्ष और अनसुलझे विवाद फिर उभर आते हैं, जिससे उन्हें दोबारा अपराध की दुनिया में कदम रखना पड़ता है। फिल्म में भावनाओं, एक्शन और नॉस्टैल्जिया का संतुलित मिश्रण देखने को मिलेगा।

भ्रष्टाचार की मिट्टी में दफन कानून लेखपाल और ईओ के बयानों में फंसा पेंच

आखिर किसका है खेल

नगर पालिका और भू-माफिया का गठजोड़ सामने रास्ता होने के बावजूद विवादित जमीन पर मिट्टी डालना सवालों के घेरे में

कौशाम्बी सिराथू नौडिया आमद करारी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर चल रहा विवाद अब तहसील और भरवारी नगर पालिका के बीच नूरा कुश्ती में तब्दील हो गया है ग्राम सभा की गाटा संख्या 261 नवीन परती हरिजन आबादी पर न्यायालय में धारा 67 के अंतर्गत मुकदमा लंबित होने के बावजूद धड़ल्ले से हो रही मिट्टी भराई ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली की कलई खोल दी है जब हमारी टीम ने इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए क्षेत्रीय लेखपाल का साफ कहना है कि मिट्टी भराई का कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है इसमें उनका कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है वहीं दूसरी ओर अधिशाषी ईओ अधिकारी का कहना है कि उन्हें वहां गड्ढा होने और किसी शादी समारोह के आयोजन के संबंध में प्रार्थना पत्र मिला था जिसके आधार पर मिट्टी डलवाई गई अधिकारियों के इन दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब उक्त स्थल के बिल्कुल सामने से आने जाने का मुख्य रास्ता मौजूद है तो प्रशासन अचानक उसी विवादित स्थान पर मिट्टी डालने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है

जो पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है सूत्रों और स्थानीय ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि यह सब एक रसूखदार सभासद के इशारे पर हो रहा है ताकि गड्ढा भरने और शादी के बहाने सरकारी जमीन पर विपक्षी का स्थाई कब्जा पक्का कराया जा सके

पत्रकार की कलम से क्या प्रशासन खूनी संघर्ष का इंतजार कर रहा है

अदालती कार्यवाही को दरकिनार कर प्रशासन द्वारा एक पक्ष को लाभ पहुँचाना न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि क्षेत्र में खूनी संघर्ष को दावत देने जैसा है शिकायतकर्ता प्रमोद सिंह के प्रार्थना पत्र पर यदि समय रहते निष्पक्ष जाँच नहीं हुई तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है प्रार्थना पत्र पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के बावजूद अधिकारियों की ढुलमुल नीति भ्रष्टाचार और मिलीभगत की बू दे रही है

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 260 किसानों को धनराशि 42 लाख 46 हजार 526 हस्तान्तरित

कृषक दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत 45 किसानों को धनराशि 02 करोड़ 24 लाख 70 हजार हस्तान्तरित

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व राजस्व तथा आपदा विभाग के अन्तर्गत किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति एवं किसानों के बीमा से सम्बन्धित लाभ वन क्लिक डी.बी.टी. के माध्यम से सम्बन्धित कृषकों के खाते में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा धनराशि हस्तान्तरण के सजीव प्रसारण कार्यक्रम को देखा गया। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कृषि विभाग के किसान कल्याण केन्द्र, मंझनपुर, समस्त तहसीलों एवं विकास खण्डों पर स्थित बीज गोदामों पर कृषकों एवं कर्मियों की उपस्थिति में किया गया।

कृषि विभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत जनपद में खरीफ सीजन में 1370 कृषकों द्वारा किये गये आवेदनों के सापेक्ष 260 किसानों को कुल धनराशि रू0 4246526.00 (रू0 बयालिस लाख छियालिस हजार पांच सौ छब्बीस) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत हुये क्षतिपूर्ति का लाभ दिया गया।

मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन 22 फरवरी को

जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को किया जाएगा लाभान्वित

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आस्था मिश्रा ने अवगत कराया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी के तत्वावधान में दिनांक 22 फरवरी को जनपद न्यायालय परिसर में पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में जनपद के नागरिकों को विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में जागरूक करने के साथ ही सशक्तीकरण प्रदान किया जाएगा। विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल के माध्यम से केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित

थाना सराय अकिल में पीस कमेटी की बैठक, होली और रमजान शांतिपूर्ण मनाने की अपील

कौशाम्बी। आगामी होली और रमजान पर्व को लेकर थाना सराय अकिल परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। जिसमें त्योहारों को आपसी सौहार्द, शांति और कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर मनाने पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी चायल अरुण कुमार यादव व सीओ चायल अभिषेक सिंह ने किया। बैठक में उपजिलाधिकारी चायल ने अपने संबोधन में कहा कि होली और रमजान सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। सभी समुदाय आपसी तालमेल और परंपराओं का सम्मान करते हुए पर्व मनाएं।यदि किसी जुलूस, आयोजन या अन्य गतिविधि को लेकर कोई अनुमति अथवा मार्ग संबंधी जानकारी आवश्यक हो तो समय रहते प्रशासन से संपर्क कर लें, जिससे किसी प्रकार की असुविधा न हो।